(लाख रु०)

1	2	3	4
6. हिमाचल प्रदेश . . .	3784	5635	7300
7. जम्मू और कश्मीर . . .	7999	8968	10800
8 कर्नाटक	22468	24150	30900
9. केरल . . .	12069	14152	17600
10. मध्य प्रदेश . .	27550	35577	41300
11. महाराष्ट्र	46870	66180	73500
12. मणिपुर	1766	2319	2826
13 मेघालय	2022	2446	2911
14 नागालैंड . . .	1770	1927	2453
15 उड़ीसा	13177	15400	19100
16 पंजाब	22597	26550	26000
17. राजस्थान . .	15240	17530	23500
18 सिक्किम . . .	1220	1247	1580
19. तमिलनाडु . . .	22387	26012	30500
20 त्रिपुरा . . .	1507	1578	2270
21. उत्तर प्रदेश	53437	65475	75500
22 पश्चिम बंगाल . . .	23300	31592	37140
जोड़—राज्य	375226	470844	558494

बिहार में गेड आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, हेरोदेह का बन्द होना

79. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में कोदरमा के निकट हेरोदेह स्थित गेड आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, जो कि बिहार में स्पन पाइप की एकमात्र फैक्ट्री है, जुलाई 1976 से बन्द पड़ी है और यह आरोप लगाया गया है कि उसने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के दो करोड़ रुपये का घोटाला किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि औद्योगिक बैंक ने इस कारखाने का दिवाला निकाल कर किसी प्राइवेट व्यक्ति के साथ इसकी नीलामी के लिए एक तारीख निश्चित कर दी है :

(ग) यदि उपरोक्त भागों (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक है तो जबरन छुट्टी किए गए 600 कर्मचारियों को स्थायी राहत देने के लिए सरकार के विचाराधीन क्या स्थायी हल है ; और

(घ) यदि राहत देने का कोई प्रस्ताव है तो वह कब तक दी जाएगी ?

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटारमन): (क) और (ख). 1960 में गेड आयरन और स्टील कम्पनी का प्रवर्तन किया गया और 1969 में उसमें उत्पादन होने लगा था। प्रारम्भ से ही तकनीकी एवं प्रबन्धकीय अधिकारियों के अभाव में कम्पनी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसमें भारी परिणाम में हानियां हुई। जुलाई 1976 से ही वह बन्द पड़ी है। आई० डी० बी० आई० आई० एस० सी० ओ० तथा अन्य संगठनों के प्रयास तथा उनके द्वारा किए गए प्रबन्धकीय कर्मचारियों के उपक्रम को पुनरुज्जीवित करने के प्रयत्न असफल हो गए हैं। सरकार द्वारा उपक्रम को पुनः चालू करने के प्रश्न की विस्तार से जांच की गई है तथा उद्योग को वर्तमान गिरी हुई दशा व विशेषकर कास्ट आयरन स्पन पाइप की मांग की दर की बढोतरी धीमी होने के कारण यह विवेकसम्मत नहीं समझा गया कि कम्पनी के लिए भारी निवेश किया जाये। अतएव, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के ही अन्तर्गत यह निर्णय किया गया है कि इस औद्योगिक उपक्रम के कार्यों में हस्ताक्षेप न किया जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों से उपक्रम दिवालिया ठहरायी गई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के शासकीय परिसमापक ने 18 जनवरी, 1980 को ग्राम नीलामी में उपक्रम की कुछ स्थायी सम्पत्ति बेच डाली है। शेष परिसम्पत्तियों को भी बेच देने का और प्रयत्न किया जा रहा है।

(ग) केन्द्र सरकार के पास प्रभावित कर्मचारियों का पुनर्वास करने की कोई भी वैकल्पिक योजना विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Review of Industrial Policy

80. SHRI K. A. RAJAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the liberalised capital goods import policy being followed by the Union Government has gravely affected the indigenous heavy engineering enterprises due to lack of orders; and

(b) if so, whether Government have a proposal under consideration to review and revise the policy?

THE MINISTER OF FINANCE AND INDUSTRY (SHRI R. VENKATARAMAN): (a) In the context of improving foreign exchange reserves, the Government considered how this could be taken advantage of for acelerating economic growth by removing those constraints which came in the way due to earlier paucity of foreign exchange. The Government's decision was taken to liberalise imports of capital goods with effect from 1978-79 with a view to reducing the overall cost of investment in 14 select industries of national priority, consistent with the requirements of offering protection to the indigenous capital goods industry as also introduce other measures of import liberalization. The main objective was to stimulate industrial growth and to expose indigenous capital goods industry to a controlled measure of competition. An Empowered Committee was set up for taking a view on the merit of the imports or otherwise. So far only 14 applications have come up for consideration of the Empowered Committe under the global tendering system, as such, it is yet early to assess if there has been any adverse impact on the indigenous capital goods industry. However, it may be stated that the indigenous capital goods manufacturing industry may not have been able to complete as effectively as envisaged under this scheme due to factors such as shortage of power and critical raw material inputs and other constraints of infrastructure.

(b) The Government reviews the import policy from time to time on a continuing basis.

Demand Capacity and Import of Cement

81. SHRI GEORGE FERNANDES: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the projected requirement of cement for the next five years;

(b) the installed capacity to produce cement in the country;

(c) the additional capacity presently being installed; and

(d) how much cement Government propose to import during the next year?